



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

## EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 544]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 30, 2005/पौष 9, 1927

No. 544]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 30, 2005/PAUSA 9, 1927

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 दिसम्बर, 2005

सं. 37/2005—के.ड.शु. (गै.टै.)

सा.का.नि. 756(अ).— केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) धारा 9क की उपधारा (2) के साथ पठित, धारा 37 की उप-धारा (2) के खंड (झघ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, नामतः-

**1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ-**(1) इन नियमों को केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपराधों का प्रशमन) नियमावली, 2005 कहा जाए।

(ii) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

**2. परिभाषा-** इस नियमावली में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "अधिनियम" का आशय केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944(1944 का 1) से है;

(ख) "आवदेक" का आशय किसी निर्धारिती अथवा किसी अन्य व्यक्ति से है लेकिन इसमें केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमावली, 2002 के नियम 3 के तहत बोर्ड अथवा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त द्वारा नियुक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी शामिल नहीं होगे;

(ग) "प्रशमन प्राधिकारी" का आशय उस मुख्य केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त से है जिसके अधिकार क्षेत्र में वह जगह आती हो जहाँ केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944(1944 का 1) के तहत अपराध किया गया है अथवा किए जाने का आरोप है;

(घ) "फार्म" का आशय इस नियमावली के साथ संलग्न फार्म से है;

(ड.) "रिपोर्टिंग प्राधिकारी" का आशय उस केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त से जिसके अधिकार क्षेत्र में वह जगह आती है जहाँ उक्त अधिनियम के अंतर्गत अपराध किया गया है अथवा किए जाने का आरोप है अथवा ऐसे किसी अन्य अधिकारी से है जिसे इस संबंध में उस मुख्य आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद द्वारा प्राधिकृत किया गया हो जिसके अधिकार क्षेत्र में वह कारखाना/ स्थान आता है जहाँ इस अधिनियम के अन्तर्गत ऐसे अपराध किए गए हैं अथवा किए जाने का आरोप लगाया गया है;

(च) "धारा" का आशय इस अधिनियम की किसी धारा से है; तथा

(छ) ऐसे शब्द एवं अभिव्यक्तियां जिनका इस नियमावली में प्रयोग किया गया है और जो इसमें परिभाषित नहीं की गई हैं लेकिन अधिनियम में परिभाषित की गई हैं, उनका वही अभिप्राय होगा जो अधिनियम में उनके लिए निर्दिष्ट किया गया है।

**3. फार्म एवं आवेदन का तरीका-**(1) आवेदक या तो अभियोजन की संस्थापना के पूर्व अथवा इसके पश्चात्, अपराध के प्रशमन हेतु प्रशमन प्राधिकारी को इस नियमावली के साथ संलग्न फार्म में धारा 9क की उप-धारा (2) के तहत आवेदन करेगा।

**स्पष्टीकरण:** जहां कोई अपराध एक से अधिक प्रशमन प्राधिकारियों के क्षेत्राधिकार में आने वाले एक से अधिक स्थानों पर किया गया हो, तो ऐसे स्थान पर क्षेत्राधिकार रखने वाला मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सक्षम प्राधिकारी होगा जहां जब भाल का मूल्य, अथवा अपवंचित शुल्क अथवा शुल्क अपवंचस के प्रयास की राशि अन्य स्थानों से ज्यादा है।

### 3. नियम 3 के तहत आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् की प्रक्रिया-

- (1) नियम 3 के तहत आवेदन प्राप्त होने पर, प्रशमन प्राधिकारी रिपोर्टिंग प्राधिकारी से इस आवेदन में दिए गए विवरणों अथवा ऐसी कोई अन्य सूचना, जिसे ऐसे आवेदन की जांच के लिए संगत समझा जाए, के संदर्भ में रिपोर्ट मांगेगा।
- (2) रिपोर्टिंग प्राधिकारी द्वारा ऐसी रिपोर्ट प्रशमन प्राधिकारी से संसूचना की प्राप्ति की तिथि से एक माह की अवधि के अंदर अथवा प्रशमन प्राधिकारी की अनुमति से बढ़ाई गई अवधि के अंदर प्रस्तुत की जाएगी।
- (3) प्रशमन प्राधिकारी उक्त आवेदन के विवरणों को ध्यान में रखकर, आदेश द्वारा, या तो नियम 5 की शर्तों के अनुसार प्रशमन राशि दर्शाते हुए आवेदन की अनुमति दे सकता है और उसे अभियोजन से उन्मुक्ति प्रदान कर सकता है या ऐसे आवेदन को अस्वीकृत कर सकता है। बशर्ते कि आवेदन तब तक अस्वीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदक को उसका पक्ष सुनने का अवसर न दिया गया हो तथा अस्वीकृत करने के आधारों का ऐसे आदेश में उल्लेख न किया गया हो।
- (4) उप-नियम (3) के तहत प्रत्येक आदेश की एक प्रति आवेदक को भेजी जाएगी।
- (5) आवेदक, अपराधों के प्रशमन की अनुमति देने वाले उप-नियम (3) के तहत आदेश की प्राप्ति की तिथि से 30 दिन की अवधि के अंदर प्रशमन प्राधिकारी द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार प्रशमन राशि का भुगतान कर।
- (6) एक बार चुकाए जाने के बाद प्रशमन राशि उन मामलों को छोड़कर जहाँ न्यायालय ने अभियोजन से प्रदान की गई उन्मुक्ति को निरस्त कर दिया हो, की प्रति अदायगी नहीं की जाएगी।
- (7) आवेदक अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता कि उसके अपराध का प्रशमन किया जाएगा।

**5. प्रशमन राशि का निर्धारण-** इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के तहत अपराधों के प्रशमन के प्रयोजनार्थ प्रशमन राशि यहां नीचे दिए गए अनुसार होगी -

क्रम सं.	अपराध	प्रशमन राशि
1.	अधिनियम की धारा 9(1)(क) के तहत विनिर्दिष्ट अपराध	प्रथम अपराध के लिए पचास हजार रुपये और इसके पश्चात् किए जाने वाले प्रत्येक अपराध के लिए राशि बढ़ाकर इस राशि को सौ प्रतिशत कर दी जाएगी ।
2.	अधिनियम की धारा 9 (1)( ख) के तहत विनिर्दिष्ट अपराध	माल के बाजार मूल्य के बीस प्रतिशत तक अथवा दस लाख रुपए , जो भी अधिक हो ।
3.	अधिनियम की धारा 9 (1)( ख)(ख) के तहत विनिर्दिष्ट अपराध	माल के बाजार मूल्य के बीस प्रतिशत तक अथवा दस लाख रुपए , जो भी अधिक हो ।
4.	अधिनियम की धारा 9 (1)( ख ख ख) के तहत विनिर्दिष्ट अपराध	माल के बाजार मूल्य के बीस प्रतिशत तक अथवा दस लाख रुपये, जो भी ज्यादा हो ।
5.	अधिनियम की धारा 9 (1)( ख ख ख ख) के तहत विनिर्दिष्ट अपराध	ऐसे क्रेडिट के सौ प्रतिशत तक
6.	अधिनियम की धारा 9(1)(ग) के तहत विनिर्दिष्ट अपराध	प्रथम अपराध के लिए पचास हजार रुपये और इसके पश्चात् किए जाने वाले प्रत्येक अपराध के लिए राशि बढ़ाकर इस राशि को सौ प्रतिशत कर दी जाएगी ।
7.	अधिनियम की धारा 9(1)(घ) के तहत विनिर्दिष्ट अपराध	माल के बाजार मूल्य के बीस प्रतिशत तक अथवा दस लाख रुपये, जो भी ज्यादा हो ।

**6. अभियोजन से उन्मुक्ति प्रदान करने की प्रशमन प्राधिकारी की शक्ति-**

(1) यदि प्रशमन प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि इस नियमावली के तहत अपराध के प्रशमन हेतु आवेदन करने वाले व्यक्ति ने उसके समक्ष कार्यवाहियों में सहयोग किया है तथा मामले से जुड़े तथ्यों का पूरा और सही खुलासा किया है तो वह ऐसे व्यक्ति को अपराध के प्रशासन के दायरे में आने वाले मामले के संदर्भ में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के तहत किसी अपराध के लिए ऐसी शर्तों के अध्यधीन अभियोजन से उन्मुक्ति प्रदान कर सकता है जिन्हें लगाना वह उचित समझता हो ।

**7. कतिपय स्थितियों में अभियोजन से उन्मुक्ति वापस लिया जाना-**

(1) किसी व्यक्ति को नियम (6) के तहत प्रदान की गई उन्मुक्ति वापस ले ली जाएगी यदि ऐसा व्यक्ति नियम 4 के उप-नियम (3) के तहत प्रशमन प्राधिकारी द्वारा पारित किए गए प्रशमन आदेश में विनिर्दिष्ट की गई किसी राशि का ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट समय के अंदर भुगतान करने में असफल रहता है अथवा ऐसे किसी अन्य शर्त का पालन करने में असफल रहता है जिसके अध्यधीन उन्मुक्ति प्रदान की गई थी तथा इसके पश्चात् केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के उपबंध उस प्रकार लागू होंगे मानो ऐसी कोई उन्मुक्ति प्रदान नहीं की गई थी ।

(2) उपर्युक्त उप नियम (1) के तहत किसी व्यक्ति को प्रदान की गई उन्मुक्ति प्रशमन प्राधिकारी द्वारा किसी भी समय वापस ले ली जाएगी, यदि वह इस बात से संतुष्ट है कि ऐसे व्यक्ति ने प्रशमन कार्यवाहियों के दौरान किन्हीं विवरणों, सामग्री को छिपाया था अथवा झूठी गवाही दी

थी और इसके पश्चात् ऐसे व्यक्ति पर ऐसे अपराध के लिए, जिसके संबंध में उसे उन्मुक्ति प्रदान की गई थी अथवा ऐसे किसी अन्य अपराध के लिए जिसके लिए ऐसा लगता हो कि प्रशमन कार्यवाहियों के संबंध में उसने ऐसा अपराध किया है, अभियोजन चलाया जा सकता है और इसके पश्चात् केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो ऐसी कोई उन्मुक्ति प्रदान नहीं की गई थी।

**फार्म  
(नियम 3 देखें)**  
**अपराध के प्रशमन के लिए आवेदन**

1. आवेदक का पूरा नाम एवं पता :
2. पन्नाचार का पता:
3. (i) स्थायी लेखा संख्या (पैन):  
(ii) पंजीकरण सं.
4. आवेदक पर क्षेत्राधिकार रखने वाला केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तः
5. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के उन उपबंधों का उल्लंघन जिनके लिए अभियोजन संस्थित किया गया है अथवा किये जाने का विचार है जिसके लिए प्रशमन हेतु आवेदन किया जा रहा है:
6. प्रशमन मामले के संबंध में बीजक /न्यायनिर्णयन आदेश का विस्तृत विवरण:
7. जब्ती की तिथि, यदि कोई हो:
8. मामले के संक्षिप्त तथ्य तथा लगाए गए आरोपों का विवरण:
9. क्या कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है:
10. यदि हां, तो दावा किए गए शुल्क/निर्यात प्रोत्साहनों का विवरण:
11. क्या कारण बताओ नोटिस का न्यायनिर्णयन कर दिया गया है:
12. यदि हां, तो न्यायनिर्णयन के विवरण:
- (क) पुष्ट किए गए शुल्क की राशि
- (ख) वसूले जाने वाले/मना किए जाने वाले सेनेवेट क्रेडिट की राशि
- (ग) लगाया गया जुर्माना
- (घ) लगाया गया अर्थदण्ड
13. क्या यह केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के तहत पहला अपराध है। यदि नहीं, तो पिछले मामलों का विवरण:
14. क्या इसी अपराध के लिए कोई कार्यवाही अपेक्षित है, यदि हां तो उसका विवरण:

आवेदक का नाम एवं पता

### घोषणा

1. मैं वह प्रशमन राशि चुका दूंगा जो प्रशमन प्राधिकारी द्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (अपराधों का प्रशमन) नियमावली, 2005 के नियम 4 के उप-नियम (3) के तहत प्रशमन प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की जा सकती है।
2. मैं यह समझता हूँ कि मैं अधिकार के रूप में यह दावा नहीं कर सकता कि इस अधिनियम के तहत मेरे द्वारा किये गए अपराध का प्रशमन किया जाए।

### **आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर**

#### सत्यापन

मैं-----पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री-----निवासी-----विधिवत रूप से घोषणा करता हूँ कि मैं----- की हैसियत से यह आवेदन कर रहा हूँ और मैं इसे सत्यापित करने हेतु सक्षम हूँ।

यह कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार इस आवेदन के विवरण सही हैं तथा इस मामले के तथ्यों से संबंधित कोई भी सूचना छिपायी नहीं गई है। इस आवेदन के साथ लगे दस्तावेज मूल प्रतियों की सत्यप्रतियां हैं तथा वित्तीय लेन देन दर्शने वाली सारणियां सही हैं और मेरे द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित हैं।

आज दिनांक ----- (दिन) ----- (माह) ----- (वर्ष) को ----- में सत्यापित किया गया।

### **आवेदक का नाम एवं हस्ताक्षर**

**स्थान:**

**तिथि:**

[फा. सं. 267/22/2005-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क-8]

राहुल नांगरे, अवर सचिव

**MINISTRY OF FINANCE**

(Department of Revenue)

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th December, 2005

**No. 37/2005—Central Excise (N.T.)**

**G.S.R. 756(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (id) of sub-section (2) of section 37 read with sub-section (2) of section 9A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby makes the following rules, namely:

**1. Short title and commencement. -**

- (i) These rules may be called the Central Excise (Compounding of Offences) Rules, 2005.
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

**2. Definitions.-** In these rules , unless the context otherwise requires,

- (a) “Act” means the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944);
- (b) “applicant” means any assessee or any other person, but shall not include officers of Central Excise as appointed by Board or Commissioner of Central Excise under Rule 3 of the Central Excise Rules 2002;
- (c) “compounding authority” means the Chief Commissioner of Central Excise, having jurisdiction over the place where the offence under the Central Excise Act, 1944, have been or alleged to have been committed;
- (d) “form” means the form appended to these rules;
- (e) “reporting authority” means, the Commissioner of Central Excise, having jurisdiction over the factory/place where the offences under the Act have been or are alleged to have been committed or any other officer as may be authorized in this regard by the Chief Commissioner of Central Excise having jurisdiction over the place where such offences under the Act have been or are alleged to have been committed;
- (f) “section” means a section of the Act; and
- (g) words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act shall have the respective meanings assigned to them in the Act.

**3. Form and manner of application.** – (1) An applicant may, either before or after institution of prosecution, make an application under sub-section 2 of section 9A in the form appended to these rules, to the Compounding authority to compound the offence:

Explanation.- Where an offence under the Act has been committed at more than one place falling under the jurisdiction of more than one compounding authority, then the Chief Commissioner of Central Excise having jurisdiction over such place where the value of goods seized, or the amount of duty evaded or attempted to be evaded is more than the others shall be the competent authority.

**4. Procedure on receipt of application under rule 3** - (1) On receipt of an application under rule 3, the compounding authority shall call for a report from the reporting authority with reference to the particulars furnished in the application, or any other information, which may be considered relevant for examination of such application.

(2) Such report shall be furnished by the reporting authority within a period of one month or within such extended period as may be allowed by the compounding authority, from the date of receipt of communication from the compounding authority.

(3) The compounding authority, after taking into account the contents of the said application, may, by order, either allow the application indicating the compounding amount in terms of rule 5 and grant him immunity from prosecution in terms of rule 6 or reject such application:

Provided that application shall not be rejected unless an opportunity has been given to the applicant of being heard and the grounds of such rejection are mentioned in such order.

(4) A copy of every order under sub rule (3) shall be sent to the applicant.

(5) The applicant shall, within a period of thirty days from the date of receipt of order under sub-rule (3) allowing the compounding of offences, pay the compounding amount, as ordered to be paid by the compounding authority and shall furnish the proof of such payment to the compounding authority.

(6) The compounding amount once paid shall not be refunded except in cases where the court rejects grant of immunity from prosecution.

(7) The applicant cannot claim, as of right, that his offence shall be compounded.

**5. Fixation of the Compounding amount.**— For the purpose of compounding of offences under the various provisions of the Act, the compounding amount shall be as provided herein below,-

Sl.No.	Offence	Compounding amount
1	Offence specified under section 9(1)(a) of the Act	Rupees fifty thousand for the first offence and to be increased by hundred per cent of this amount for each subsequent offence.
2	Offence specified under section 9(1)(b) of the Act	Upto twenty per cent of market value of goods or Rs. Ten lakhs whichever is higher.
3	Offence specified under section 9(1)(bb) of the Act	Upto twenty per cent of market value of goods or Rs. Ten lakhs whichever is higher.
4	Offence specified under section 9(1)(bbb) of the Act	Upto twenty per cent of market value of goods or Rs. Ten lakhs whichever is higher.
5	Offence specified under section 9(1)(bbbb) of the Act	Upto hundred per cent of such credit.
6	Offence specified under section 9(1)(c) of the Act	Rupees fifty thousand for the first offence and to be increased by hundred per cent of this amount for each subsequent offence.
7	Offence specified under section 9(1)(d) of the Act	Upto twenty per cent of market value of goods or Rs. Ten lakhs whichever is higher.

**6. Power of Compounding authority to grant immunity from prosecution.** -

The compounding authority, if he is satisfied that any person who has made the application for compounding of offence under these rules has co-operated in the proceedings before him and has made full and true disclosure of facts relating to the case, grant to such person, subject to such conditions as he may think fit to impose, immunity from prosecution for any offence under the Central Excise Act, 1944 with respect to the case covered by the compounding of offence.

## 7. Withdrawal of Immunity from Prosecution in certain conditions. -

(1) An immunity granted to a person under rule 6 shall stand withdrawn if such person fails to pay any sum specified in the order of compounding passed by the compounding authority, under sub-rule (3) of rule 4 within the time specified in such order or fails to comply with any other condition subject to which the immunity was granted and thereupon the provisions of the Central Excise Act, 1944 shall apply as if no such immunity had been granted.

(2) An immunity granted to a person under sub rule (1) above may, at any time, be withdrawn by the Compounding authority, if he is satisfied that such person had, in the course of the compounding proceedings, concealed any particulars, material or had given false evidence, and thereupon such person may be tried for the offence with respect to which immunity was granted or for any other offence that appears to have been committed by him in connection with the compounding proceedings and thereupon the provisions the Central Excise Act, 1944 shall apply as if no such immunity had been granted.

### FORM

(see rule 3)

### Application for Compounding of Offence

1. Full Name and address of the applicant:
2. Address for communication:
3. (i) Permanent Account Number (PAN):  
(ii) Registration No:
4. Commissioner of Central Excise having jurisdiction over the applicant:
5. The violation of provisions of Central Excise Act, 1944, against which prosecution is instituted or contemplated for which application of Compounding:
6. Details of invoices/Adjudication order in relation to the case for compounding:
7. Date of seizure, if any:
8. Brief facts of the case and particulars of the offence(s) charged:
9. Whether Show Cause Notice issued
10. If yes, details of duty demanded
11. Whether Show Cause Notice has been adjudicated
12. If yes, adjudication details
  - (a) Amount of duty confirmed
  - (b) Amount of CENVAT credit to be recovered/denied
  - (c) Fine imposed
  - (d) Penalty imposed

13. Whether this is the first offence under the Central Excise Act, 1944. If not details of previous cases:
14. Whether any proceedings for the same offence contemplated under any other law, if so the details thereof:

**Name and Signature of the applicant.**

**DECLARATION**

1. I shall pay the compounding amount, as may be fixed by the compounding authority under sub-rule (3) of Rule 4 of the Central Excise (Compounding of Offences) Rules, 2005.
2. I understand that I cannot claim, as of right that the offence committed by me under the Act should be compounded.

**Name and Signature of the applicant.**

**VERIFICATION**

I, -----the son/daughter/wife of-----residing at -----do solemnly declare that I am making this application in my capacity as----- and I am competent to verify it.

That the contents of this application are true to the best of my knowledge and belief and no information relevant to the facts of the case has been suppressed. The documents accompanying the application are true copies of the originals and the tables showing financial transactions are correct and are duly attested by me.

Verified today the                   day of   (month)                   (year) at .

**Name and Signature of the applicant.**

Place:

Date:

[F. No. 267/22/2005-CX-8]

RAHUL NANGARE, Under Secy.